



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1573]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2009/आश्विन 8, 1931

No. 1573]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2009/ASVINA 8, 1931

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2009

का.आ. 2496(अ).—इस मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना सं. 603(अ) के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों को दिनांक 17-9-1991 से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्र सरकार के मतानुसार उक्त जिले ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में थे कि सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक था।

2. 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों की घोषणा की पिछली बार मार्च, 2009 में समीक्षा की गई थी और 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों की घोषणा की अवधि को 30 सितम्बर, 2009 तक बढ़ाया गया।

3. इन दो जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति की अब और समीक्षा की गई है। वर्ष 2009 के दौरान (15 अगस्त, 2009 तक) इन दो जिलों में अपहरण, हमले, अन्तर-गुटीय संघर्ष, हत्या आदि से संबंधित हिंसा की 34 घटनाएँ हुई हैं। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इसाक/मुइवाह) और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) जबरन धन वसूली और हिंसा की कार्रवाइयों में लगे हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप इन दोनों जिलों में लोगों के मन में भय व्याप्त है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ

नागालैंड के इन दो गुटों के बीच तेज हुई अन्तर-गुटीय दुश्मनी से इन दोनों जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति और बिगड़ गई है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम द्वारा इन दोनों जिलों का प्रयोग म्यांमार में अपने शिविरों के लिए ट्रांजिट मार्गों के रूप में भी किया जा रहा है।

4. अतः केन्द्र सरकार का यह मत है कि सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में की घोषणा को 1 अक्टूबर, 2009 से अगले छह (6) माह की अवधि तक, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए, जारी रखा जाना आवश्यक है।

[फा. सं. 13/27/99-एन. ई. II]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2009

S.O. 2496(E).—Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 vide this Ministry's Notification No. 603(E) dated 17-9-1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary.

2. The declaration of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in March, 2009 and the tenure of declaration of these two districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended upto 30th September, 2009.

3. A further review of the law and order situation in these two districts has since been undertaken. During 2009 (Upto 15th August, 2009) there have been 34 incidents of violence relating to abduction, assault, inter-group clash, killing etc. in these two districts. The National Socialist Council of Nagaland (Issac/Moviah) and National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) continue to engage themselves in extortions and acts of violence as a result of which fear psychosis prevails in these two districts. Intense inter-group rivalry between

the two factions of National Socialist Council of Nagaland has further vitiated the law and order situation in these two districts. These two districts are also being used by cadres of National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) and United Liberation Front of Asom as transit routes to their camps in Myanmar.

4. The Central Government is, therefore, of the opinion that continuation of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' under the Armed Forces (Special Power) Act, 1958 is necessary for a further period of six (6) months with effect from 1st October, 2009, unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-NE. II]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.